

माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. तुली और ए. एस. बैस के समक्ष

श्री हरि राम- याचिकाकर्ता।

बनाम

संपदा शुल्क के सहायक नियंत्रक-सह-आयकर वृत्त एवम अन्य, - उत्तरदाता।

1973 का सी डब्ल्यू पी नंबर 4633।

21 नवंबर, 1974।

भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 14 - संपदा शुल्क अधिनियम (1953 का XXXIV) - धारा 34 (1) (सी) - क्या भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

अभिनिर्धारित किया कि एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 की धारा 34 (एल) (सी) के प्रावधान किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण नहीं हैं। एक सहभागी जो वंशजों के बिना मर रहा है और एक सह-संरक्षक जो वंशजों को छोड़ रहा है, समान नहीं है और न ही एक सहभागी अन्य व्यक्तियों के बराबर है, जिनकी संपत्ति संपत्ति शुल्क के लिए उत्तरदायी है। वे व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों का निर्माण करते हैं और यह उनके लिए महत्वपूर्ण है।

विधायिका कराधान के उद्देश्यों और उनसे वसूले जाने वाले करों की दर का चयन करती है। लाइनल वंशजों को छोड़ने वाले सभी सहभागियों के सम्पदा को एक ही तरीके से संपत्ति शुल्क के प्रभार में लाया जाएगा और अलग-अलग नहीं। इस वर्ग के दो सहकर्मियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, और इसलिए अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत नहीं है।

(पैरा 12) जिन मामलों से असहमति जताई गई

(एक) वी दावकी अम्मल बनाम सहायक संपदा नियंत्रक, मद्रास (1973)91 आई.टी.आर.

स्वीकृत मामले

(दो) टी. आर. जयशंकर बनाम सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक (1973)83 आई.टी.आर. 445 पृष्ठ 448.

(तीन) एन. कृष्ण प्रसाद बनाम सहायक संपदा नियंत्रक गुंटूर (1972) आई.टी.आर.

(चार) श्रीमती कोमंदुरी शेशममे बनाम संपदा शुल्क के अपीलीय नियंत्रक (1973)88 आई.टी.आर.

(पाँच) एन. वी. सोमराजू बनाम भारत सरकार और अन्य (1973) टैक्स एलआर 1084।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 की धारा 34 (1) (सी) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर घोषित किया जाए और कहा जाए कि धारा 34 (एल) (सी) का धारा 5 से कोई लेना-देना नहीं है। आरोप धारा और धारा 6 से 15 के साथ, जो संयुक्त परिवार में वंशजों के हित के संबंध में मृत्यु से संबंधित संपत्ति से संबंधित है और अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो संयुक्त परिवार में वंशजों के हितों को मानता है, जिन पर मृतक की मृत्यु होने पर संपत्ति हस्तांतरित की जाती है ताकि चार्जिंग सेक्शन को आकर्षित किया जा सके और अलग रखा जा सके। प्रतिवादी संख्या 10 का आदेश। (ख) रिट याचिका के अनुलग्नक क में 1 नवंबर, 1973 की अधिसूचना सं 2 में 10,000 करोड़ रुपये की राशि को शामिल करने का संबंध है। 2,23,096 रुपये (1,00,000 करोड़ रुपये की राशि सहित) आवासीय घर में वंशजों के हिस्से का मूल्य होने के नाते 10,000 रुपये) लाइनल वंशजों का हिस्सा होने के नाते मृतक श्री साधु राम की संपत्ति के मूल मूल्य में शामिल किया गया है, और प्राप्त संपत्ति शुल्क की अतिरिक्त राशि वापस की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से एस. के. हीराजी अधिवक्ता के साथ वकील भागीरथ दास।

ई. प्रतिवादी 1 और 3 की ओर से एन. अवस्थी अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता एस. एस. महाजन अन्य प्रतिवादियों के लिए

### निर्णय

तुली, न्यायमूर्ति- (1) साधु राम की मृत्यु 3 जुलाई, 1969 को हुई थी, वह अपने पीछे अपनी विधवा श्रीमती पिस्तो देवी और चार बेटों को छोड़ गए थे, जिनमें से याचिकाकर्ता हरि राम सबसे बड़े हैं। उन्होंने एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया और

साधु राम की मृत्यु पर, उनकी संपत्ति के खिलाफ संपत्ति शुल्क लगाने की कार्यवाही की गई। हरि राम ने एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 की धारा 53 (3) (जिसे बाद में 'अधिनियम' कहा जाता है) के तहत जवाबदेह व्यक्ति के रूप में रिटर्न दाखिल किया। हरि राम द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार, श्री साधु राम ने 1,67,564 रुपये की चल संपत्ति छोड़ दी थी, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में 58,206 रुपये के मूल्य का 6 वां हिस्सा था और 15,000 रुपये के आवासीय घर में समान हिस्सा था, जिसे अधिनियम की धारा 33 (1) (एन) के तहत संपत्ति शुल्क के भुगतान से छूट देने का दावा किया गया था।

(2) सहायक संपदा नियंत्रक ने 22 फरवरी, 1971 के अपने आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 34 (1) (ई) के अनुसार दर के प्रयोजनों के लिए अपनी संपत्ति के मूल मूल्य में मृतक साधु राम के वंशजों के 4/6 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए 2,32,824 रुपये की राशि जोड़कर जवाबदेह व्यक्ति (श्री हरि राम) का आकलन किया। उन्होंने आवासीय घर में लाइनल वंशजों के 4/6 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए 10,000 रुपये की राशि भी जोड़ी। हालांकि, कहा जाता है कि यह आकलन साधु राम द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मूल मूल्य पर किया गया था, जिसमें उनके वंशजों और विधवा का हिस्सा शामिल नहीं था। उस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 62 के तहत क्षेत्रीय संपदा शुल्क नियंत्रक, दिल्ली में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 63 के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसे 1 नवंबर, 1973 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। अपीलीय न्यायाधिकरण ने श्री साधु राम की मृत्यु से पहले उनकी बीमारी पर किए गए चिकित्सा खर्चों के लिए 10,000 रुपये की राशि की अनुमति दी, जिसे निचले अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन यह माना कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति और आवासीय घर में 4/6 हिस्से का मूल्य दर के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के कुल मूल्य में शामिल किया गया था। अधिकरण के समक्ष, अपील के निम्नलिखित आधारों को उठाने की अनुमति मांगी गई थी -

"सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक ने कानून में गलती की, जिसमें मृतक की मृत्यु पर दी गई संपत्ति के मूल्य में 2,32,824 रुपये की राशि शामिल है, जो धारा 34 (1) (सी) के तहत दर उद्देश्यों के लिए वंशजों के हिस्से का मूल्य है। अपीलीय नियंत्रक ने उक्त समावेश की पुष्टि करने में भी गलती की। एस्टेट ड्यूटी एक्ट की धारा 34 (1) (सी) असंवैधानिक है और इसलिए, अवैध और शून्य है, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 5 वें मामले में कहा था। दावकी अम्मल वी। एस्टेट ड्यूटी के सहायक नियंत्रक, मद्रास<sup>1</sup> •"

(तीन) विद्वान ट्रिब्यूनल ने अपील के उस आधार पर इस कारण से विचार नहीं किया कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को इसके तहत गठित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रस्ताव के लिए, केएस वेंकटरमन एंड कंपनी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था। (पी) लिमिटेड मद्रास राज्य<sup>2</sup>, और रास्तापुर शरणप्पा बनाम मैसूर उच्च न्यायालय का एक निर्णय। एस्टेट ड्यूटी के नियंत्रक<sup>3</sup>। ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न कानून के सवालों के संदर्भ के लिए इस न्यायालय में निर्णय के लिए एक आवेदन दायर करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर वर्तमान याचिका दायर की कि धारा 34 (1) (सी) की संवैधानिक वैधता को केवल रिट याचिका के माध्यम

<sup>1</sup> (1973) 91 आई.टी.आर.

<sup>2</sup> (1966) 60 आई.टी.आर.

<sup>3</sup> (1970) 77 आई.टी.आर.

से चुनौती दी जा सकती है, न कि उसी कारण से संदर्भ कार्यवाही में जैसा कि अपीलिय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया था। याचिका को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई है, जिनकी ओर से यह आग्रह किया गया है कि अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) संवैधानिक रूप से वैध है और मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय, इसके विपरीत, वी में है। देवकी पशु वी। सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक, कोयम्बटूर, सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

(4) इस अधिनियम की धारा 5 के तहत, संपत्ति शुल्क लगाया जाना है और मूल मूल्य पर भुगतान किया जाना है, जैसा कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में प्रावधान किया गया है, सभी संपत्ति, जो कि निपटाए गए या निपटाए नहीं गए हैं, जो अधिनियम की धारा 35 के अनुसार निर्धारित दरों पर मृतक की मृत्यु पर पारित होता है और किसी अन्य संपत्ति का मूल्य इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। लागू की जाने वाली दर का निर्धारण करने के लिए।

(5) अधिनियम की धारा 2(16) में "मृत्यु पर पारित संपत्ति" को परिभाषित किया गया है जिसमें "मृत्यु के तुरंत बाद या किसी भी अंतराल के बाद, या तो निश्चित रूप से या आकस्मिक रूप से, और या तो मूल रूप से या अधीन सीमा के माध्यम से" और "मृत्यु पर" को शामिल किया गया है और "मृत्यु पर" में "मृत्यु के संदर्भ में पता लगाने योग्य अवधि" शामिल है। अधिनियम की धारा 3 (3) में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पारित संपत्ति के लिए अधिनियम में संदर्भ का अर्थ यह लगाया जाएगा कि इसमें ऐसी संपत्ति के संदर्भ शामिल हैं जो उस व्यक्ति की मृत्यु पर पारित होने के लिए समझी जाती है। "संपत्ति जिसे पारित माना जाता है" को अधिनियम की धारा 6 से 16 में वर्णित किया गया है, जिसमें से, हमारे उद्देश्यों के लिए, केवल धारा 6 और 7 (1) प्रासंगिक हैं। धारा 6 के अनुसार, संपत्ति जिसे मृतक अपनी मृत्यु के समय £ का निपटान करने के लिए सक्षम था, उसे उसकी मृत्यु पर पारित करने के लिए माना जाएगा। धारा 7(1) निम्नलिखित शब्दों में है:-

"इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जिस संपत्ति में मृतक या किसी अन्य व्यक्ति का मृतक की मृत्यु पर ब्याज था, उसे मृतक की मृत्यु पर उस सीमा तक पारित करने के लिए माना जाएगा, जिस हद तक इस तरह के ब्याज के उपकर से लाभ प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है, जिसमें विशेष रूप से, मिताक्षरा द्वारा शासित हिंदू परिवार की संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिकी हित शामिल है। मारुमकट्टयम या अलियासंताना कानून।

अधिनियम की धारा 34 उन मामलों को निर्धारित करती है जिनमें शुल्क की दरों को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए संपत्तियों के मूल्यों को निम्नानुसार एकत्र किया जाना है: -

(1) मृतक की मृत्यु पर गुजरने वाली किसी भी संपत्ति पर भुगतान किए जाने वाले संपत्ति शुल्क की दर का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, -

(क) धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (ग), (घ), (ङ), (i), (j), (1), (m), (mm), (n), (o) और (p) के अधीन संपत्ति के अलावा अन्य संपत्तियों को संपत्ति के अलावा अन्य सभी संपत्तियों को संपत्ति शुल्क से छूट दी गई है;

(आ) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी भी राज्य में इस प्रकार पारित की गई कृषि भूमि, यदि कोई हो; और

(इ) इस प्रकार की संपत्ति के मामले में, जिसमें मिताक्षरा, मारू द्वारा शासित हिंदू परिवार की संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायित्वकारी हित शामिल है-

\* मक्कट्टायन या अलियासंतना कानून, भी हित

मृत सदस्य के सभी वंशजों की संयुक्त परिवार की संपत्ति में;

एक संपत्ति बनाने के लिए एकत्रित किया जाएगा और उस पर मूल मूल्य के संबंध में लागू दर या दरों पर संपत्ति शुल्क लगाया जाएगा।

(दो) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी किसी भी संपत्ति में संपत्ति शुल्क से छूट प्राप्त कोई संपत्ति शामिल है, तो उस संपत्ति पर लगाया गया संपत्ति शुल्क जो इस तरह से छूट प्राप्त नहीं है, वह संपत्ति होगी।

शुल्क की कुल राशि जो पूरी संपत्ति पर देय होती, यदि इसका कोई हिस्सा इतना छूट नहीं दिया गया होता, तो संपत्ति के मूल्य के समान अनुपात पूरी संपत्ति के मूल्य के बराबर होता है।

स्पष्टीकरण--इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति को संपत्ति शुल्क से छूट" का अर्थ है-

(१) कोई भी संपत्ति जो धारा 33 के तहत संपत्ति शुल्क से मुक्त है;

(२) किसी भी राज्य में स्थित कोई कृषि भूमि जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है;

(३) मिताक्षरा, मारुमक्कट्टयम या अलियासंतना कानून द्वारा शासित हिंदू परिवार की संयुक्त परिवार की संपत्ति में मृतक के अलावा अन्य सभी सहवासियों के हित।

(तीन) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी संपत्ति जिसमें मृतक का कभी कोई हित नहीं था, एक अधिकार या ऋण या लाभ नहीं है, जिसे धारा 2 के खंड (15) के

स्पष्टीकरण के आधार पर संपत्ति के रूप में माना जाता है, को किसी भी संपत्ति के साथ एकत्रित नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने आप में एक संपत्ति होगी, और संपत्ति शुल्क उसके मूल मूल्य के संबंध में लागू दर या दरों पर लगाया जाएगा।

(चार) प्रत्येक संपत्ति में मृतक की मृत्यु की तारीख तक शामिल और बकाया संपत्ति पर अर्जित सभी आय शामिल होगी।

(पाँच) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई भी संपत्ति एक से अधिक बार एकत्रित नहीं की जाएगी और न ही एक ही मृत्यु पर उसके संबंध में संपत्ति शुल्क एक से अधिक बार लगाया जाएगा।

(छः) धारा 391 भी मृत्यु होने पर सहदायिकी संपत्ति में ब्याज के मूल्यांकन को रोकने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। इस धारा की उपधाराएं (1) और (3) केवल तत्काल मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार पढ़ी जाती हैं: –

39. (1) किसी संयुक्त परिवार में सहदायिकी ब्याज के उपकर से प्राप्त या उत्पन्न होने वाले लाभ का मूल्य मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित संपत्ति जो किसी सदस्य की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है, संयुक्त परिवार में उस हिस्से का प्रमुख मूल्य होगी जो मृतक को आवंटित किया गया होता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले विभाजन हुआ होता।

(तीन) मिताक्षरा, मरुमकट्टायम या अलियासंतना कानून द्वारा शासित हिंदू परिवार की संयुक्त परिवार की संपत्ति के मूल मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से, ताकि मृतक को आवंटित किए गए हिस्से की भरपाई की जा सके, अगर उसकी मृत्यु से ठीक पहले विभाजन हुआ होता, तो इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, यदि संयुक्त परिवार की पूरी संपत्ति मृतक की होती तो वे उसी तरह से लागू होते जैसे वे लागू होते।

(7) अधिनियम के इन प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति शुल्क लगाया जाता है और इसका भुगतान संपत्ति के मूल मूल्य पर किया जाना है जो अधिनियम की धारा 35 में उल्लिखित दर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गुजरता है या माना जाता है और प्रभारयोग्य संपत्ति का मूल्य धारा 34 और 39 पूर्वोक्त के अनुसार निर्धारित किया जाना है। इस मामले में, साधु राम को मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित किया गया था और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों के साथ एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया था। संयुक्त परिवार के भीतर पिता और उनके चार बेटों की सहदायिकी थी और उनकी मृत्यु पर पारित संपत्ति के मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 7 और 39 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के केवल 1/6 वें हिस्से के मूल्य को ध्यान में रखा जाना था। शुल्क की दर निर्धारित

करने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के तहत कार्रवाई की जानी थी, अर्थात्, लाइनल वंशजों के शेयरों का मूल्य धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उल्लिखित संपत्तियों के साथ एकत्र किया जाना था। इसके बाद, धारा 34 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार साधु राम मृतक की कर योग्य संपत्ति पर देय संपत्ति का आकलन किया जाना था। मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी भी पक्ष ने यह दर्शाने वाली गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं की है कि संपदा शुल्क का मूल्यांकन कैसे किया गया था, लेकिन विभाग के विद्वान वकील श्री अवस्थी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मूल्यांकन धारा 34 के अनुसार किया गया था और यदि नहीं, तो संपदा शुल्क अधिकारी निम्नानुसार देय शुल्क की गणना करेगा।

यह इंगित किया जाना चाहिए कि संपत्ति शुल्क का मूल्यांकन कर योग्य संपत्ति पर और अधिनियम की धारा 34 (1) और (2) में प्रदान किए गए तरीके से किया जाना है, न कि पूरी संपत्ति पर जिसमें लिनल वंशजों के शेयर भी शामिल हैं। अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के तहत लिनल वंशजों के शेयरों को बाहर रखा जाना है।

(8) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत हैं, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 5 वीं में कहा है। देवकी अम्मल का मामला (सुप्रा)। राजस्व विभाग की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व के एक फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें पीएल एस आरएम रामनाथन चेट्टियार बनाम सहायक संपदा नियंत्रक, कोयम्बटूर<sup>4</sup> का मामला दिया गया था। देवकी अम्मएवीएस केस (सुप्रा), लेकिन बिना किसी टिप्पणी के। हालांकि, राजस्व द्वारा पेश की गई व्यापक व्याख्या के आधार पर, विद्वान न्यायाधीशों ने धारा 34 (1) (सी) की वैधता के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े और विपरीत दृष्टिकोण के समर्थन में अपने स्वयं के कारण दिए। श्री डी एन अवस्थी ने केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के टी. आर. जयशंकर बनाम केरल मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। सहायक संपदा नियंत्रक<sup>5</sup> बनाम एन कृष्ण प्रसाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन खंडपीठ के फैसले सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक, गुंटूर<sup>6</sup>, श्रीमती कोमंदुरी शेषम्मा वी. एस्टेट ड्यूटी के नियंत्रक<sup>7</sup>, और एन. वी. सोमराजू वी। भारत सरकार और अन्य<sup>8</sup>, उनके द्वारा प्रचारित विपरीत दृष्टिकोण के लिए।

---

<sup>4</sup> (1970) 76 आई.टी.आर. 402

<sup>5</sup> 1973) 83 आई.टी.आर. 445

<sup>6</sup> (1972) आई.टी.आर.

<sup>7</sup> (1973) 88 आई.टी.आर

<sup>8</sup> 1973 टैक्स एलआर 1084

(नौ) पीएल एस आरएम रामनाथन चेट्टियार के मामले (सुप्रा) में, यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसलिए, अमान्य है क्योंकि इसके प्रावधान केवल संयुक्त परिवार के मामलों पर लागू होते हैं।

मिताक्षरा कानून न कि दयाभागा कानून द्वारा शासित परिवारों के लिए। निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विवाद को दूर कर दिया गया था -

"यद्यपि संयुक्त हिंदू परिवार के संबंध में दयाभागा कानून और मिताक्षरा कानून की अवधारणा में एक बुनियादी अंतर है, फिर भी, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि अंतर को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के परंतुक के कारण हटा दिया गया है, और यह मामला होने के नाते, एकत्रीकरण का सिद्धांत केवल मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त परिवार के मामलों पर लागू होता है, न कि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित परिवारों पर। दयाभागा विधि। हमें ऐसा लगता है कि पूरा तर्क गलत है। दयाभागा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में, एकत्रीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है, क्योंकि, ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु अपने व्यक्तिगत कानून के कारण परिवार की संपत्ति में एक परिभाषित हिस्सेदारी के रूप में होती है, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित एक मृत सदस्य के विपरीत। यही कारण है कि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में, एकत्रीकरण के सिद्धांत को धारा 34 (1) (सी) में सन्निहित किया गया है। लेकिन एकत्रीकरण के सिद्धांत के लिए, ऐसे मामले पर लागू दर उस लाभ के मूल्य के अनुरूप दर होगी जिसे मृतक के प्रत्येक वंशज को अर्जित माना जा सकता है। जबकि, दयाभागा परिवार के मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृत सदस्य का हिस्सा क्रिस्टलीकृत है, उस मामले में लागू दर मृतक सदस्य के हिस्से के मूल्य के अनुरूप दर होगी। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि, लेकिन धारा 34 (1) (सी) द्वारा परिकल्पित एकत्रीकरण के सिद्धांत के लिए, भेदभाव होगा। वास्तव में, धारा 34 (1) (सी) इस तरह के भेदभाव से बचती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक हिंदू संयुक्त परिवार है जिसमें दो भाई शामिल हैं और उनमें से एक दो बेटों को छोड़कर मर जाता है। यदि धारा 34 (1) (सी) नहीं होती, तो प्रत्येक पुत्र इस बात पर जोर देने का हकदार होगा कि उसे अर्जित लाभ के मूल्य पर लागू दर इस तरह के मूल्य के अनुरूप होगी। धारा 34 (1) (सी) के मद्देनजर, दोनों बेटों में से प्रत्येक को प्राप्त होने वाले लाभ का मूल्य एकत्र किया जाएगा और समग्र मूल्य पर लागू दर क्या होगी?

धारा 39 के तहत पता लगाया गया है कि मृतक के बेटों में से एक को प्राप्त होने वाले लाभ के मूल्य पर लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया से ठीक वही परिणाम प्राप्त होता है जो दयाभागा हिंदू परिवार के किसी



सदस्य की मृत्यु के मामले में होता है, यह मानते हुए कि परिवार में सदस्य शामिल हैं जैसा कि हमने मिताक्षरा हिंदू संयुक्त परिवार के मामले में माना है।

इसलिए यह माना जाएगा कि कराधान की दरों को लागू करने के मामले में मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार और दयाभागा परिवार के सदस्यों के बीच धारा 34 (1) (सी) द्वारा जो कुछ भी लाया गया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है।

टी.आर. में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश। जयशंकर के मामले (सुप्रा) ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ भेदभाव के विवाद को दूर कर दिया:

उन्होंने कहा, 'यह सच है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कराधान कानून पर भी लागू होता है। लेकिन कराधान के मामले में विभिन्न तत्वों के राजकोषीय समायोजन की अंतर्निहित जटिलता को ध्यान में रखते हुए, विधायिका के पास जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, विधियों और यहां तक कि कराधान की दरों को चुनने और चुनने में एक बड़ा विवेकाधिकार है, जब तक कि यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानूनों के समान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यदि कोई कराधान कानून एक सामान्य वर्गीकरण पर आधारित है, तो उस पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि यह कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह पर भेदभावपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा जो उनके साथ जुड़ी कुछ विशेष विशेषताओं के कारण एक और उप-वर्गीकरण पर एक वर्ग में आएं। धारा 34 की उप-धारा (1) (सी) में निहित एकत्रीकरण के प्रावधान में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि एक हिंदू की मृत्यु पर पारित संपत्ति पर देय शुल्क की दर, चाहे मिताक्षरा, मारुमक्कट्टयम या अलियासंताना कानून द्वारा शासित हो, एक सामान्य आधार पर तय की जाती है, अर्थात्, मृतक सदस्य के सभी वंशजों की संयुक्त संपत्ति में ब्याज उसकी मृत्यु पर गुजरने वाले मृतक की संपत्ति के साथ एकत्रित किया जाएगा। तथ्य यह है कि मारुमक्कट्टयम कानून का पालन करने वाले एक मृत व्यक्ति की रुचि

पारिवारिक संपत्ति तुलनात्मक रूप से छोटी हो सकती है, जब एक परिवार में मिताक्षरा कानून का पालन करने वाले व्यक्ति की तुलना में, दोनों के सदस्यों और संपत्ति की संख्या समान है, उनके लिए लागू अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों और उनके बच्चों की संख्या के कारण, कानून द्वारा किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार का परिणाम नहीं है, लेकिन यह विशेष मामलों के अलग-अलग तथ्यों पर एक ही कानून के संचालन का परिणाम है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष, एन. कृष्ण प्रसाद के मामले में यह आग्रह किया गया था कि: –

(एक) धारा 34. (1) (ग) संसद की विधायी शक्ति की क्षमता से परे था, क्योंकि मृतक की मृत्यु पर पारित संपत्ति में उसके ब्याज के मूल्य पर संपत्ति शुल्क लगाने के बजाय, इसने मृतक के वंशज की संपत्ति में प्रवेश किया, हालांकि ऐसी संपत्ति मृतक की मृत्यु पर पारित नहीं हुई; और

(दो) मिताक्षरा स्कूल के एक हिंदू अविभाजित परिवार में एक कोपार्सेनर की मौत के मामले में एकत्रीकरण के सिद्धांत को लागू करना, न कि दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ में एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य पर, संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल भेदभाव के समान है।

तर्कों को खारिज करते हुए, यह कहा गया था -

(एक) कि संपत्ति शुल्क के संबंध में कानून बनाने के लिए संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 87 के तहत संसद को दी गई शक्ति में आवश्यक रूप से संपत्ति शुल्क की दरों को तय करने की शक्ति शामिल है। जब संसद संपत्ति शुल्क पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो यह कर की दर और जिस तरह से कर की गणना की जानी है, उसके बारे में कानून बना सकती है और उसे बनाना चाहिए। अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) में वंशज की संपत्ति में घुसपैठ नहीं की गई है, बल्कि केवल संपत्ति शुल्क की दर तय करने के उद्देश्य से इसे ध्यान में रखा गया है, कोपार्सेनर की मृत्यु पर पारित संपत्ति के मूल्य पर इसे लाइनल वंशज के हिस्से की संपत्ति के मूल्य के साथ एकत्र करके;

(दो) मिताक्षरा और दयाभागा स्कूलों के तहत संयुक्त हिंदू परिवार से जुड़ी घटना 1 में, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में एक हिंदू अविभाजित परिवार में एक पिता दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ के तहत हिंदू अविभाजित परिवार में पिता से अलग वर्ग से संबंधित है; कि वर्गीकरण समझदार भिन्नता पर आधारित है जो पिता के एक समूह को दोनों के तहत पिता के दूसरे समूह से अलग करता है। हिंदू कानून के स्कूल और यह कि वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ एक संबंध और उचित संबंध भी है जिसके लिए एस्टेट ड्यूटी अधिनियम लागू किया गया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) संविधान के अनुच्छेद 14 (हेड-नोट्स के अनुसार) के प्रतिकूल नहीं है।

श्रीमती कोमंदुरी शेषमा के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि:

(तीन) (1) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 87, जिसे अनुच्छेद 360 (9) के साथ पढ़ा जाता है, मूल्यांकन के उद्देश्य से केवल मृतक की संपत्ति को ध्यान

में रखने की अनुमति देता है, जिसमें संपत्ति शुल्क की वसूली, दर का पता लगाना और संपत्ति शुल्क की वसूली भी शामिल है। इसने लाइनल वंशजों की संपत्ति को दर उद्देश्यों के लिए एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी। मृतक की मृत्यु पर पारित संपत्ति के साथ वंशज के हिस्से को एकत्रित करने की शक्ति न तो आकस्मिक थी और न ही संपत्ति शुल्क लगाने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के लिए सहायक थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(दो) यहां तक कि यह मानते हुए कि अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) संविधान के अनुरूप है, फिर भी यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (एफ) का उल्लंघन करता है और इसलिए, अमान्य है।

(तीन) सरकार अधिनियम के तहत मृतक के वंशजों की संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगा सकती थी। सरकार जो प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं कर सकती थी- <sup>^</sup> वंशजों के हिस्से पर संपत्ति शुल्क लगाने वाला कानून बनाकर वह एक अप्रत्यक्ष विधि से प्राप्त करना चाहती थी, जिसमें वंशजों के हिस्से को किसके हिस्से के साथ एकत्र किया गया था?

दर के प्रयोजनों के लिए संयुक्त परिवार की संपत्तियों में मृतक। संसद ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थी।

(चार) अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) मिताक्षरा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के बीच हिंदू अविभाजित परिवार के एक सदस्य के रूप में एक अपमानजनक वर्गीकरण करती है, जिससे एक वंशज और एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है। यह एक अनुचित वर्गीकरण है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(पाँच) अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) द्वारा मृतक की संपत्ति प्राप्त करने के लिए मृतक के उत्तराधिकारियों के अधिकार में अनुचित रूप से कटौती की गई है। इसलिए, धारा 34 (1) (सी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के तहत किसी व्यक्ति को गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

इन तर्कों को खारिज करते हुए, यह कहा गया था: –

(एक) अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) संसद की विधायी क्षमता के भीतर है, और संविधान के अनुच्छेद 366 (9) के साथ पढ़ी जाने वाली संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 87 द्वारा इसे दी गई शक्ति के भीतर है।

(दो) किसी मृतक की मृत्यु पर पारित संपत्ति पर कैसे और किस दर से कर लगाया जाना है, इस बारे में कानून बनाने की शक्ति, संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 87 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के लिए एक आकस्मिक और सहायक शक्ति है।

(दो) न तो एस्टेट ड्यूटी एक्ट और न ही धारा 34 (1) (सी) लाइनल वंशज के हिस्से पर कोई शुल्क लगाती है जो किसी मृतक की मृत्यु को पारित नहीं करती है। यह क्या करता है कि यह मृत्यु पर गुजरने वाली संपत्ति पर संपत्ति शुल्क लगाता है। केवल उस दर को निर्धारित करने के उद्देश्य से जिस पर मृतक की मृत्यु पर गुजरने वाली संपत्ति पर कर लगाया जाना है, धारा 34 (1) (सी) अधिनियमित की गई है। उस उद्देश्य के लिए यह कहता है कि वंशजों के शेयरों को संपत्ति के साथ एकत्र किया जाना चाहिए।

एक मृतक की मौत। मृत्यु पर गुजरने वाले मृतक की संपत्ति पर कैसे और किस दर से कर लगाया जाना है, यह एक ऐसा मामला है जिसे विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी मृतक की मृत्यु पर पारित संपत्ति के संदर्भ में कर की दर निर्धारित करने की शक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 366 (9) के भीतर आती है और संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 87 के तहत संपत्ति शुल्क पर कानून बनाने की शक्ति में शामिल है।

(चार) केवल इस आधार पर कि एक वर्ग में, किसी को विशेष और असामान्य परिस्थितियों में दूसरे पर लाभ मिलता है, एक कर कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कानून ने ऐसे व्यक्ति को विशेष उपचार के लिए अलग नहीं किया है। एस्टेट ड्यूटी एक्ट में मिताक्षरा हिंदू अविभाजित परिवार में न तो पिता और न ही बेटे को विशेष उपचार के लिए रखा गया है। यह अधिनियम न तो अनुचित वर्गीकरण करता है और न ही एक और दूसरे के बीच भेदभाव करता है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करता है।

(पाँच) यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि धारा 34 (1) (सी) मृतक के हिस्से के साथ अपने शेयरों को एकत्र करके और मृतक के हिस्से को पूरी समग्र संपत्ति पर लागू कर की दर के अधीन करके वंशजों की संपत्ति में घुसपैठ नहीं करती है। यह तर्क कि एकत्रीकरण के कारण, मृतक की मृत्यु के बाद पारित संपत्ति कराधान की उच्च दर के अधीन है और उस हद तक वंशजों को

अपने पिता का पूरा हिस्सा हासिल करने के अधिकार से वंचित करती है, सही नहीं है। चाहे पिता का हिस्सा एक दर या दूसरे के अधीन था, लिनल वंशजों को केवल अपने पिता का हिस्सा मिलता है जिसमें लगाए गए कर शामिल नहीं होते हैं। यदि इस तर्क को बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अधिनियम, एकत्रीकरण के सिद्धांत के बिना भी, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) का उल्लंघन है। संपत्ति शुल्क मृतक की मृत्यु पर पारित संपत्ति पर लगाया जाता है, इससे पहले कि यह लाइनल वंशजों का हिस्सा बन जाए। वही कानून मृत्यु पर पारित संपत्ति पर एक दायित्व लगाता है। यह केवल संपत्ति शुल्क के भुगतान के बाद है जो उस पर देय है, कि संपत्तियों की शेष राशि को लाइनल वंशजों द्वारा साझा किया जाएगा। इस प्रकार इस तर्क में कोई बल नहीं है कि अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) का उल्लंघन करती है।

एन. वी. सोमराजू के मामले (सुप्रा) में, यह कहा गया था: –

(एक) धारा 34 (1) और (2) के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पिता की मृत्यु के बाद पिता से पुत्र को पारित होने वाले ब्याज को किस दर पर माना जाता है, यह पता लगाने के उद्देश्य से, दोनों ब्याज एकत्र किए जाते हैं, फिर भी संपत्ति शुल्क केवल उस ब्याज पर लगाया जाता है जिसे पिता की मृत्यु के बाद पिता से पुत्र को पारित माना जाता है। संसद न केवल यह नियम निर्धारित करने के लिए सक्षम है कि सिद्धांत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाना है, बल्कि दर निर्धारित करने के लिए एक सूत्र विकसित करने के लिए भी सक्षम है, जिस पर कुल सिद्धांत मूल्य चार्ज किया जाना है। यह पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को दी गई संपत्ति या ब्याज पर संपत्ति शुल्क लगाने के लिए समान रूप से सक्षम है। धारा 34 में कुछ भी पढ़ने का मतलब यह है कि इस प्रकार पाई गई दर पर रहने वाले बेटे की संपत्ति या ब्याज सहित पूरी संपत्ति पर संपत्ति शुल्क लगाया जाता है। अंततः जो शुल्क लगाया जाता है वह पिता द्वारा छोड़ी गई सटीक संपत्ति या ब्याज है और जिसे बेटे को पारित माना जाता है।

1

(दो) संविधान के अनुच्छेद 366 (9) में संपत्ति शुल्क की परिभाषा में प्रावधान का उद्देश्य संपत्ति या ब्याज को कवर करना है जो मिताक्षरा हिंदू कानून के तहत उत्तरजीविता के नियम से गुजरता है।

में

(तीन) धारा 34 (1) (सी) मिताक्षरा पिता के बीच किसी भी तरह से भाई या उसके बेटों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं है। एक ही वर्ग के बीच कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होने के कारण, अनुच्छेद 14 को आकर्षित नहीं कहा जा सकता है। मिताक्षरा पिता को एक पिता की तुलना में कुछ हद तक लाभप्रद स्थिति पर रखा गया है दयाभागा विधि। यदि ऐसा है, तो कोई भी मिताक्षरा पिता या मिताक्षरा पुत्र, जिसके लाभ के लिए प्रावधान प्रतीत होता है, संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के आधार पर धारा 34 (1) (सी) की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता है।

(चार) संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों पर विचार करते समय, कोई सटीक या गणितीय सटीकता पर विचार नहीं किया जाता है और जो देखा जाना चाहिए वह एक ही वर्ग को दी गई समग्र समानता है। वर्गीकरण उचित और तर्कसंगत है और इसका उस उद्देश्य के साथ आवश्यक संबंध है जिसे एस्टेट ड्यूटी अधिनियम के प्रावधान प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं।

(पाँच) कराधान के मामले में विधायिका को न केवल विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को वर्गीकृत करने की अधिक स्वतंत्रता है कि किसके लिए या कौन सा कर लगाया जाना है, बल्कि कराधान के विभिन्न तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, धारा 34 (1) (सी) को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

(दस) इन फैसलों को मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था, जिसने संभवतः इस कारण से बनाम देवकी अम्मल के मामले (सुप्रा) का फैसला किया था कि 10 अक्टूबर, 1972 तक उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया था, जब उस मामले में फैसला सुनाया गया था। डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने केवल पीआई एसएम रामनाथन चेट्टियार के मामले (सुप्रा) में फैसले पर विचार किया और उस फैसले से असहमति व्यक्त किए बिना, उन्होंने राजस्व द्वारा अपनाई गई व्यापक व्याख्या के आधार पर अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) की वैधता के सवाल पर विचार किया। राजस्व विभाग की ओर से यह दलील दी गई थी। देवकी अम्मल का मामला (सुप्रा) कि -

"धारा 34 (1) (सी) का उद्देश्य मृतक के सहदायिकी हित के साथ लिनल वंशज के सहदायिकी हित को भी जोड़ना है ताकि एक पूरी संपत्ति बनाई जा सके और धारा की वैधता पर उसी प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए।

(ग्यारह) उस मामले में, सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक ने बेटे के आधे हिस्से को उसके मृतक के आधे हिस्से के साथ जोड़ दिया था।

पिता ने एक संपत्ति बनाने के लिए और अपने मूल्यांकन आदेश में मृतक पिता के आधे हिस्से पर ऐसी संयुक्त संपत्ति पर लागू दर लागू की थी और यह वह आदेश था जिसे बेंच के समक्ष चुनौती दी जा रही थी। अमीरुन्निसा बेगम और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। महबूब बेगम और अन्य<sup>9</sup>, और श्री राम कृष्ण डालमिया और अन्य न्यायमूर्ति एसआर तेंडोलकर और अन्य<sup>10</sup> इस प्रस्ताव के समर्थन में कि अनुच्छेद 14 का अधिदेश यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, बशर्ते कि उस अनुच्छेद में निहित कोई भी बात राज्य को मांगी गई वस्तुओं के तर्कसंगत संबंध रखने वाले समझदार भिन्नता पर स्थापित उचित वर्गीकरण के आधार पर कानून बनाने से नहीं रोकेगी। कानून द्वारा हासिल किया जाना है। इसके बाद वेणुगोपाल रवि वर्मा राजा बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निम्नलिखित उद्धरण को पुनः प्रस्तुत किया गया । भारत संघ<sup>11</sup>, यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित सिद्धांतों को सामने लाने के लिए कि किन मामलों में कर संविधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है: -

"संविधान का समान संरक्षण खंड अमूर्त प्रस्तावों के रूप में कानूनों के समान संरक्षण को शामिल नहीं करता है। कानून विशिष्ट समस्याओं को हल करने या विशिष्ट उपायों द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायी इच्छा की अभिव्यक्ति होने के नाते, उपचार की पूर्ण समानता या एकरूपता उपलब्धि से असंभव है। फिर से कर कानूनों का उद्देश्य अनंत विविधता की जटिल समस्याओं से निपटना है, जिसके लिए कई अलग-अलग तत्वों के समायोजन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, न्यायालय यह स्वीकार करते हैं कि समानता के सिद्धांत के मौलिक सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन, वर्गीकरण के मामले में विधायी विवेक ाधिकार के लिए एक बड़ा खेल है। वर्गीकृत करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ताकि कराधान की प्रणाली को सभी उचित और उचित तरीकों से समायोजित किया जा सके; विधायिका व्यक्तियों,

---

<sup>9</sup> ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 91

<sup>10</sup> ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 538

<sup>11</sup> (1969) 74 आई.टी.आर. 49

संपत्तियों, लेनदेन और वस्तुओं का चयन कर सकती है, और कर के लिए विभिन्न तरीकों और यहां तक कि दरों को लागू कर सकती है, अगर विधायिका यथोचित रूप से ऐसा करती है। समानता खंड का संरक्षण एक गणितीयरूप से सटीक या तार्किक रूप से पूर्ण नहीं है।

या सममित वर्गीकरण: यह समान सुरक्षा की गारंटी की शर्त नहीं है कि एक ही जीनस के सभी लेनदेन, गुण, वस्तुएं या व्यक्ति इससे प्रभावित होने चाहिए या बिल्कुल भी नहीं। यदि वर्गीकरण तर्कसंगत है, तो विधायिका कराधान की वस्तुओं को चुनने, विभिन्न दरों को लागू करने, कराधान से संपत्ति के वर्गों को छूट देने, संपत्ति के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग तरीकों से कर के अधीन करने और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। एक कर क़ानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है यदि यह संपत्ति, व्यक्तियों, लेनदेन या व्यवसायों के एक ही वर्ग पर कराधान की घटनाओं को लागू करना चाहता है जो स्पष्ट असमानता की ओर जाता है। इसलिए, एक कर संविधि को भेदभाव के आधार पर केवल इसलिए हमला नहीं किया जाता है क्योंकि कराधान की विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों, लेनदेन, व्यवसायों या वस्तुओं के लिए कराधान की अलग-अलग दरें निर्धारित की जाती हैं।

यह विधायिका का काम है कि वह उन वस्तुओं का निर्धारण करे जिन पर कर लगाया जाएगा और उनकी दरें क्या हैं। न्यायालय किसी अधिनियम को केवल इसलिए कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने के रूप में निरस्त नहीं करेंगे क्योंकि अन्य वस्तुओं पर विधायिका द्वारा कर लगाया जा सकता था, लेकिन उन पर कर नहीं लगाया जा सकता था।

इन टिप्पणियों के आलोक में, अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के प्रावधानों का विश्लेषण किया गया था, और यह बताया गया था कि इसने वंशजों और अन्य व्यक्तियों को छोड़ने वाले सहवासियों के बीच एक वर्गीकरण किया था जो अनुचित था और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। इस संबंध में पीठ की टिप्पणियों को संक्षेप में निर्धारित करना बेहतर होगा जो निम्नानुसार हैं (पृष्ठ 37-41):

"कोपार्सेनर के वंशजों की मृत्यु के मामले में, संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके वंशजों के हित को मृतक के हित के साथ जोड़ा जाता है जो उसकी मृत्यु पर संपत्ति शुल्क लगाने के उद्देश्य से एक संपत्ति बनाता है, जबकि अन्य के मामले में अकेले मृत्यु पर पारित वास्तविक संपत्ति को लेवी की विषय वस्तु के रूप में लिया जाता है। यह विवाद में नहीं



है कि पूर्व मामले में अधिक कर बोझ है। बेशक, धारा 34 (1) (सी) एक कोपार्सेनर को एकल करती है जिसमें वंशज होते हैं और उच्च दर लागू करके उच्च बोझ डालता है। उनकी मृत्यु पर पारित संपत्ति पर कर। प्रश्न यह है कि क्या सम्पत्ति शुल्क लगाने में सामान्य रूप से वंशजों और अन्य लोगों के बीच इस प्रकार के विभेद का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उचित संबंध है। राजस्व के अनुसार उक्त विभेदन का अधिनियम के उद्देश्यों से इतना उचित संबंध है। यह कहा गया है कि अधिनियम का एक उद्देश्य धन के संकेंद्रण में असमानताओं को दूर करना और उसका उचित वितरण सुनिश्चित करना है और इस संबंध में मूल विधेयक में निर्धारित उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख किया गया है। राजस्व के लिए श्री बालासुब्रमण्यम द्वारा यह भी बताया गया है कि इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य दयाभागा परिवार के सदस्यों और मिताक्षरा परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति शुल्क की लेवी में असमानता को दूर करना है, कि जब एक दयाभागा परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु पर गुजरने वाली संपत्ति वह है जो उसकी शाखा से संबंधित है। लेकिन जब मिताक्षरा परिवार के किसी कोपार्सेनर की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक का ब्याज अकेले मृत्यु पर बीत जाता है और लगाया गया संपत्ति शुल्क उस सीमा से काफी कम होता है जो वह दयाभागा परिवार का सदस्य होता। ऐसा कहा जाता है कि इस असमानता को दूर करने और मिताक्षरा कानून द्वारा शासित व्यक्तियों और दयाभागा कानून द्वारा शासित व्यक्तियों के बीच कर के बोझ को न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से धारा 34 (1) (सी) में प्रावधान पेश किया गया है। हम यह देखने में सक्षम नहीं हैं कि राजस्व द्वारा इंगित किए गए आधार पर वर्गीकरण को कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस तरह के वर्गीकरण को बरकरार रखा जाना चाहिए जो कानून के उद्देश्य से उचित संबंध रखने वाले समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में अपनाई गई भिन्नता मृतक कोपार्सेनर के वंशजों का अस्तित्व है। इसका अधिनियम के उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है जो मृत्यु पर पारित संपत्ति पर एक श्रेणीबद्ध कर लगाना है। जैसा कि अल्बर्टा प्रांतीय कोषाध्यक्ष बनाम न्यायिक समिति<sup>12</sup> द्वारा बताया गया है, कानून के दायरे और उद्देश्य को चार्जिंग सेक्शन से इकट्ठा किया जाना है। चार्जिंग सेक्शन केवल एस्टेट ड्यूटी लगाने को सीमित करता है। मृत्यु से गुजरने वाली संपत्ति पर न कि किसी अन्य संपत्ति पर जो मृत्यु पर पारित नहीं होती है। इस मामले में धारा 5 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, विशेष रूप से प्रावधान करती

<sup>12</sup> (1933) ए.सी. 710 (पी.सी.)।

है कि आरोप 'मृतक की मृत्यु पर पारित संपत्ति' पर है। धारा 6 से 15 के प्रावधान, जो मृत्यु पर दी जाने वाली संपत्तियों से संबंधित हैं, संयुक्त परिवार की संपत्ति में ज्वार मृतक के वंशजों के हितों को कवर नहीं करते हैं, और अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो संयुक्त परिवार में वंशजों के हितों को मृतक की मृत्यु को पारित करने के लिए मानता है ताकि आरोप लगाने की धारा को आकर्षित किया जा सके। धारा 34 केवल एक मशीनरी अनुभाग है और यह चार्जिंग अनुभाग के दायरे को नहीं बढ़ा सकता है। यदि यह प्रावधान किया गया था कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में वंशजों के हित को मृतक की मृत्यु पर पारित करने के लिए माना जाता है, तो यह कहना संभव है कि संसद ने मृत्यु पर मरने वाले व्यक्ति के सहदायिकी हित के साथ-साथ वंशजों के हिस्से पर भी कर लगाने का सकारात्मक इरादा किया है। जबकि चार्जिंग सेक्शन संयुक्त परिवार में वंशजों के हिस्से को चार्ज करने के लिए नहीं लाता है, धारा 34 (1) (सी) में मशीनरी अनुभाग दर उद्देश्यों के लिए एकत्रीकरण की आड़ में इसे चार्ज करने के लिए लाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मशीनरी अनुभाग चार्जिंग अनुभाग के दायरे को नहीं बढ़ा सकते हैं। यह सच है कि यद्यपि धारा 34 (1) (सी) संयुक्त परिवार की संपत्ति में वंशजों के हित को मृतक की मृत्यु के बाद के हित के साथ जोड़ती है, कर वास्तव में केवल मृत्यु पर गुजरने वाले मृतक के ब्याज पर लगाया जाता है, क्योंकि उस धारा की उपधारा (2) के तहत वंशजों के हितों को संदर्भित कर के लिए छूट दी जाती है। लेकिन, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि धारा 34 (1) (सी) में मृतक की संपत्ति में वंशजों के हिस्से को भी शामिल करने से एक अलग कर लगता है और उप-धारा (2) के प्रावधानों के बावजूद, मृत्यु पर मृत्यु पर पारित संपत्ति पर उच्च कर बोझ डालता है, भले ही मृतक ने वंशज को छोड़ दिया हो। यह स्थिति तब अधिक स्पष्ट होती है जब मृत्यु पर मरने वाले मृतक के हित का मूल्य होता है।

यह 50,000 रुपये से कम है। ऐसे मामले में धारा 34 (1) (सी) के संचालन से, लिनल वंशजों का हिस्सा मृतक के हिस्से के साथ शामिल हो जाता है और संपत्ति शुल्क देय हो जाता है, जबकि इस तरह के समावेश के लिए कोई संपत्ति शुल्क देय नहीं होगा।

धारा 34 (1) (सी) एक तरह से वंशजों की संपत्ति को मृत्यु के बाद मृतक के ब्याज \* के साथ चार्ज करने के लिए लाती है। हमें अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है जो किसी ऐसी संपत्ति पर शुल्क लगाने में सक्षम बनाता हो जिसमें मृतक की मृत्यु नहीं हो सके। जब अधिनियम का उद्देश्य मृतक की मृत्यु पर संपत्ति पर संपत्ति शुल्क की एक

श्रेणीबद्ध दर लगाना है, तो अकेले कुछ व्यक्तियों की मृत्यु पर पारित संपत्तियों को केवल इसलिए उच्च कर बोझ कैसे वहन किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ वंशजों को छोड़ दिया था। माना जाता है कि हिंदू कानून की मिताक्षरा प्रणाली के तहत मृतक को संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने वंशजों के शेयरों में कोई अधिकार या हित नहीं हो सकता है, जिसे उन्होंने जन्म से अपने अधिकार के परिणामस्वरूप अर्जित किया था, और वंशजों के इस तरह के हित को एकत्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा चार्जिंग सेक्शन के तहत नहीं लाया जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि धारा 34 (1) (सी) चार्जिंग सेक्शन से कहीं आगे जाती है और यह उन सहवासियों के बीच भेदभाव करती है जो कर बोझ को लागू करने में वंशजों और अन्य लोगों को छोड़ देते हैं और पूर्व की मृत्यु पर पारित संपत्ति पर कर के उच्च प्रभाव का प्रावधान करते हैं।

जैसा कि पहले ही कहा गया है, राजस्व यह स्वीकार करता है कि वंशजों और अन्य लोगों को छोड़ने वाले सहवासियों के बीच अंतर है और पूर्व की मृत्यु पर पारित संपत्ति एक उच्च कर्तव्य के अधीन है, लेकिन इस आधार पर उस भेदभाव को बनाए रखने का प्रयास करता है कि इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कराधान की घटनाओं को रखना है। यह बताया गया है कि, यदि धारा 34 (1) (सी) में प्रदान किए गए इस तरह के एकत्रीकरण को अपनाया नहीं जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप दयाभागा परिवार के सदस्यों पर मिताक्षरा के सदस्यों की तुलना में कर का अधिक बोझ पड़ता है।

~स्त्री-विषयक

यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। यह सच हो सकता है कि कर प्रभाव हिंदू कानून के स्कूल के आधार पर अलग-अलग है, जिसके द्वारा मृतक को उसकी मृत्यु के समय शासित किया गया था। यदि वह दयाभागा परिवार के सदस्य होते, तो उनकी मृत्यु के बाद पारित संपत्ति का विस्तार और मूल्य मिताक्षरा परिवार के सदस्य होने की तुलना में काफी अधिक होता और स्वाभाविक रूप से, कर का अधिक बोझ होता है। लेकिन, यह अंतर पूरी तरह से इस तथ्य के कारण था कि मृतक को नियंत्रित करने वाला पर्सनल लॉ अलग था। दयाभागा कानून से संबंधित व्यक्ति मिताक्षरा कानून से संबंधित सदस्यों के समान व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत कानून के तहत विरासत और हस्तांतरण का अधिकार पूरी तरह से अलग है, और उनकी तुलना मिताक्षरा परिवार के सदस्यों के साथ करना जो विरासत और हस्तांतरण के विभिन्न नियमों द्वारा शासित होते हैं, एक अंतर को अनदेखा करना है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम

नौआ राजा रेड्डी<sup>13</sup>आंध्र प्रदेश मामले में उल्लेख किया है। एक वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है, जहां मतभेद नहीं हैं और जहां कोई अंतर नहीं है वहां कोई अंतर नहीं ढूंढकर। जब मृत्यु पर गुजरने वाली सहदायिकी संपत्ति का हिस्सा या सीमा अलग-अलग होती है, तो कर का बोझ भी भिन्न होता है। एक दयभागा परिवार का एक सदस्य जिसकी मृत्यु पर संयुक्त परिवार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मृत्यु पर गुजरता है, मिताक्षरा परिवार के एक सदस्य के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जिसकी मृत्यु पर तुलनात्मक रूप से संयुक्त परिवार की संपत्ति का कम हिस्सा मृत्यु पर गुजरता है, और संपत्ति शुल्क के लिए देयता, जो मृत्यु पर गुजरने वाली संपत्ति पर एक बोझ है, संपत्ति पारित होने की वास्तविक सीमा के संदर्भ के बिना दोनों के बीच न्यायसंगत नहीं बनाया जा सकता है। यदि संसद ने उनके साथ समान व्यवहार करने का इरादा किया होता, तो उसने एक प्रावधान किया होता कि, मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर, न केवल संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसकी रुचि, बल्कि उसके वंशजों के हित को भी ऐसी मृत्यु पर पारित माना जाना चाहिए, जैसा कि उसने अन्य परिस्थितियों में प्रावधान पेश किए हैं। धारा 9 में एक स्वभाव के तहत ली गई संपत्ति मृतक द्वारा एक अनिवार्य उपहार के रूप में कार्य करने का इरादा रखने के लिए किया गया यह कृत्य चाहे वह स्थानांतरण, वितरण, विश्वास की घोषणा, उत्तराधिकार में व्यक्तियों पर निपटान के माध्यम से हो, या अन्यथा, जो मृतक की मृत्यु से दो साल या उससे अधिक पहले किया गया वास्तविक नहीं होगा, को मृत्यु माना जाएगा। भले ही यह उपाधि मृतक से प्राप्तकर्ता को उपहार के रूप में दी गई हो और उस मामले में मृतक की मृत्यु पर संपत्ति का कोई वास्तविक पारित न हो। संसद का मानना है कि मृतक की मृत्यु के समय उन संपत्तियों के संबंध में संपत्ति का पारित होना पड़ा है। तथापि, हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि यदि ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है तो वह वैध होगा या नहीं। हम केवल यह इंगित कर रहे हैं कि इस तरह के एक प्रावधान के बिना वंशजों के हितों को भी धारा 5 के तहत लाना संभव नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि यद्यपि इस अधिनियम के पीछे अंतिम उद्देश्य या नीति यह सुनिश्चित करना है कि धन का उचित वितरण हो, और धन की एकाग्रता में असमानताओं को दूर करना है, यह केवल अधिनियम का विशिष्ट उद्देश्य है, अर्थात्, मृत्यु पर गुजरने वाली संपत्ति पर श्रेणीबद्ध पैमाने पर लेवी और संपत्ति शुल्क की वसूली का प्रावधान करना, यह पता लगाने के

---

<sup>13</sup> (1967) 2 आई.टी.जे. 777

लिए इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि क्या विभेदन में कोई उचित संबंध है। अन्यथा, प्रत्येक वैधानिक प्रावधान को इस आधार पर बनाए रखा जा सकता है कि इसका उद्देश्य धन के वितरण में असमानताओं को दूर करना है। अधिनियम के इरादे, दायरे और उद्देश्य को केवल अधिनियम के प्रावधानों से एकत्र किया जाना है।

संविधान के अनुच्छेद 366 (9) के तहत 'संपत्ति शुल्क' को 'सिद्धांत मूल्य पर या उसके संदर्भ में मूल्यांकन किए जाने वाले कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऐसे नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है जो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। उक्त कानूनों के प्रावधानों के तहत, ऐसा पारित किया जाए। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, संयुक्त परिवार की संपत्ति में मृतक के आश्रित आश्रितों के हित को अधिनियम में कहीं भी संपत्ति के रूप में नहीं माना गया है या मृत्यु के रूप में माना गया है। कोपार्सेनर के बीच अंतर संपत्ति शुल्क लगाने के मामले में वंशजों और अन्य लोगों को छोड़ना और मिताक्षरा संयुक्त परिवार के वंशजों को उस शुल्क की तुलना में अधिक लेवी के अधीन करना जो वे आमतौर पर शुल्क धारा के तहत उत्तरदायी होंगे, स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और मिताक्षरा परिवार के मामले में मृतक के वंशजों के हित के संदर्भ में कर की दर तय करना अनुचित है। खासकर जब यह रुचि मृत्यु पर पारित नहीं होती है। हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि संसद को कराधान के क्षेत्र में व्यक्तियों या वस्तुओं को चुनने और चुनने तथा कराधान की विभिन्न दरों को अपनाने अथवा अलग-अलग कर भार डालने का व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है। हालांकि, हमारा विचार है कि विधायिका संविधान के अनुच्छेद 366 (9) में होने वाली 'संपत्ति शुल्क' की परिभाषा और आरोप लगाने की धारा के साथ-साथ धारा 6 से 16 में निहित प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकती है, और केवल मिताक्षरा परिवार के सदस्यों को मृतक के वंशजों के शेषों को एकत्र करके उच्च कर बोझ के अधीन नहीं कर सकती है। वह मृतक जो अकेले ही मृत्यु पर गुजर जाता है। यह अलग बात होती यदि चार्जिंग सेक्शन ने वंशजों के हिस्से को भी मृत्यु के बाद संपत्ति के रूप में माना होता, लेकिन उस हिस्से को अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत छूट दी गई थी, इस मामले में शेषों की समग्रता को दर के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जा सकता था। जब कोई विशेष ब्याज या संपत्ति प्रभार के दायरे में नहीं आती है, तो इसे मृतक की संपत्ति के मूल मूल्य में शामिल करने के उद्देश्य से संपत्ति शुल्क से मुक्त संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता

है। हम जानते हैं कि विधायिका को उन मदों को ध्यान में रखने का अधिकार है जिन्हें उसने कर की दर निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से कर से छूट दी थी। लेकिन, यह सिद्धांत एक ऐसी वस्तु के रूप में लाने के लिए विस्तारित नहीं होगा जिस पर चार्जिंग अनुभाग द्वारा दर उद्देश्य के लिए भी विचार नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, भारतीय आयकर अधिनियम में, ऐसी आय जिसे कर से छूट दी जा सकती है, अभी तक इसका हिस्सा बन सकती है।

'कुल आय' का आकलन करता है जो कर योग्य आय के लिए कर की दर निर्धारित करता है। लेकिन, यह इस पर किया जाता है

इसके आधार पर लेकिन अधिनियम में प्रदान की गई छूट के लिए, इस पर कर लगाया जाना चाहिए था। इसलिए दर उद्देश्यों के लिए भी, जो वस्तुएं 'आय' नहीं हैं, वे 'कुल आय' का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। इसलिए हम संपदा शुल्क अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) को भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित करते हैं।

(बारह) इस अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के प्रावधान किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण नहीं हैं। एक कोपार्सेनर जो वंशजों के बिना मर रहा है और एक कोपार्सेनर जो वंशजों को छोड़कर मर रहा है, वे बराबर नहीं हैं और न ही एक कोपार्सेनर अन्य व्यक्तियों के बराबर वंशजों को छोड़कर मर रहा है, जिनकी संपत्ति के बराबर है; संपत्ति शुल्क के लिए उत्तरदायी है। वे व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों का निर्माण करते हैं और कराधान की वस्तुओं और उनसे प्रभारित किए जाने वाले करों की दर का चयन करना विधायिका का काम है। लाइनल वंशजों को छोड़ने वाले सभी कोपार्सेनर के सम्पदा को संपत्ति के प्रभार में लाया जाएगा; कर्तव्य एक ही तरीके से और अलग तरीके से नहीं। इस वर्ग के दो सहकर्मियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। डिवीजन बेंच के निष्कर्ष के समर्थन में अन्य तर्कों का उत्तर ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों में दिया गया है और मुझे उन्हें अपनी भाषा में पुनः प्रस्तुत करके इस निर्णय पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति बहुत सम्मान के साथ, मैं उनके द्वारा दिए गए तर्कों और निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ हूं।

(तेरह) आन्ध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद, मैं स्वयं को तर्क और उसके निष्कर्षों से पूर्णतः सहमत पाता हूं और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न हूं। देवकी अम्मल के मामले

(सुप्रा) के बारे में , मैं मानता हूं कि संविधान की धारा 34 (1) (सी) संविधान के अनुच्छेद 14 या 9 (1) (एफ) के दायरे से बाहर नहीं है।

(चौदह) ऊपर दिए गए कारणों से, इस याचिका में कोई दम नहीं है जिसे खारिज किया जाता है। पक्षों को हालांकि, अपनी लागत ों को वहन करने के लिए छोड़ दिया। इस याचिका को खारिज करना इस आधार पर है कि मूल्यांकन अधिनियम की धारा 34 के अनुसार किया गया है, अर्थात्, साधु राम के वंशजों के शेषों का मूल्य केवल संपत्ति शुल्क की दर निर्धारित करने के उद्देश्य से मृतक की अन्य संपत्ति के साथ एकत्र किया गया था।

उस पर संपत्ति शुल्क लगाया गया है और संपत्ति शुल्क उस संपत्ति पर लगाया गया है जो साधु राम की मृत्यु पर पारित हुई थी या माना गया था। यदि मूल्यांकन का आदेश इस नियम के अनुसार नहीं है, तो इसे संशोधित करना होगा ताकि इसे इसके अनुरूप लाया जा सके।

बैन्स, न्यायमूर्ति - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

Judicial Officer)

हरियाणा

(Trainee

गुरुग्राम,